अन्ना आंदोलन और राष्ट्रीय जन उभार की दिशा

प्रभात कुमार राय

जिंदा कौम पांच साल तक इंतजार नहीं किया करती, डॉ लोहिया की प्रख्यात उक्ति को भारतीय जनगण ने साकार कर दिखाया कि भारतवासी जिंदा कौम है, क्योंकि जिंदा कौम ने ही उठ खड़े होकर 16 अगस्त 2011 को भारत के आधुनिक इतिहास में शानदार पृष्ठ जोड़ा है। सरकारी लोकपाल बिल में प्रधानमंत्री को बिल के दायरे के बाहर करके यूपीए हुकूमत ने लचर और नाकारा लोकपाल बिल पेश करने के निर्णय को ललकाराते हुए अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल का ऐलान किया। अन्ना आंदोलन का दमन करने की कोशिश में कांग्रेस नेतृत्व ने बेहयाई और मूर्खता का अभूतपूर्व परिचय दिया। मनमोहनी नजर में संसद सर्वोच्च और संसद का सृजन करने वाले जनगण कुछ भी नहीं है। भारतीय जनगण ने भी विस्मित करते हुए सड़कों पर एकजुट होकर सरकारी दमन का ऐसा गजब मुंहतोड़ उत्तर दिया कि अनोखा इतिहास ही रच डाला। 1974 के जेपी आंदोलन के पश्चात 2011 का अन्ना आंदोलन संभवतया देश के लिए नवीन दिशा तय करने वाला सिद्ध होगा।

अन्ना हजारे ने वस्तुतः अपने समस्त सामाजिक कार्यों और आंदोलनों का केंद्र बिंदु सदैव ही किसान और गांव को बनाए रखा। 1991 के पश्चात नव उदारीकरण की मनमोहनी अर्थनीति अर्थनीति का सबसे अधिक खामियाजा देश के किसानों और नौजवानों को ही उठाना पड़ा। करोड़ों किसान तबाह हो गए। मुट्ठी भर कॉरपोरेट घराने, भ्रष्ट नौकरशाह और बेईमान लुटेरे राजनेता अरबों-खरबों की धनराशि के मालिक बनकर फलते-फूलते रहे। आर्थिक उदारीकरण के दौर में भ्रष्टाचार तेज गति से कुलांचे भरता रहा। राष्ट्रीय पटल पर अन्ना हजारे जैसी किसान और गांव परस्त शानदार शख्सियत का राष्ट्रीय नायक के तौर पर उभरकर आना

सत्तानशीन लुटेरे आसानी से सत्ताच्युत नहीं हुआ करते। वे आम जनगण में धार्मिक, जातिवादी और क्षेत्रीय विग्रह उत्पन्न करके और फूट डालकर अकूत दौलत के दमखम पर सत्ता हथिया लेते हैं।

और फिर भारतीय जनगण खासतौर पर नौजवानों के दिलो दिमाग में छा जाना, देश के मुस्तकबिल के लिए अवश्य ही शुभ संकेत है। अन्ना आंदोलन के लिए आगे का मार्ग कदाचित सहज और सुगम नहीं है। जेपी आंदोलन के संपूर्ण अनुभव को राष्ट्र के इतिहास में अत्यंत तल्खी के साथ दर्ज किया। 1977 की जनक्रांति का, जिसमें आपातकाल की तानाशाह सरकार का संपूर्ण सफाया हो गया था, आखिरकार उसका कैसा त्रासद हश्र देश के समक्ष आया।

राजनीतिक विपक्ष में विद्यमान किसान-मजदूर विरोधी सत्तालोलुप ताकतों ने सत्ता हथिया ली और जेपी जनक्रांति का दुखद पटाक्षेप हो गया। यह खतरा आज और भी ज्यादा बरकरार है, जबकि किसान-मजदूर विरोधी कॉरपोरेट और इसके टहलुए भ्रष्ट लुटेरे राजनेता प्रत्येक राजनीतिक दल में मजबूत घुसपैठ कर-के अपने लिए शक्तिशाली स्थान बना चुके हैं। 2014 का लोकसभा का आम चुनाव अन्ना आंदोलन के लिए सबसे कठिन कसौटी सिद्ध होगा, जबकि आंदोलन से जागृत जिंदा भारतवासी कौम प्रत्येक दल के भ्रष्ट लुटेरे राजनेता का राजनीतिक कफन-दफन अंजाम देकर क्या एक ऐसी लोकसभा के सृजन कर सकेगी, जो एक भारत की महान तकदीर को अपनी शानदार तदबीर से लिख सकेगी?

इतिहास के संजीदा सबक रहे कि सत्तानशीन लुटरे राजनेता आसानी से सत्ताच्युत नहीं हुआ करते। वे आम जनगण में धार्मिक, जातिवादी और इलाकाई विग्रह उत्पन्न करके और फूट डालकर अकूत दौलत के दमखम पर सत्ता हथिया लेते हैं। आम जनगण की अपार जागृति ही फूट डालने वाली साजिश का वाजिब जवाब है, जिसका आगाज अन्ना आंदोलन द्वारा कर दिया गया है। जनलोकपाल बिल पर छिड़ा व्यापक जन संघर्ष तो महज एक शुरुआत है। सत्तानशीनों के साथ बेहद जटिल और पुरपेंच संघर्ष समर अभी शेष है। अन्ना आंदोलन की संघर्षशील पांतों में चपला की मानिंद चमकते मध्यवर्गीय चेहरे हैं। क्रांति समर में निर्णायक विजय मेहनतकश किसान-मजदूरों की जबरदस्त शिरकत के आभाव में कदाचित संभव नहीं है। जन आंदोलन को गांवों तक फैलाना है।

अन्ना आंदोलन का मकसद महज सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना है। भ्रष्ट और लुटेरी बन चुकी राजनीतिक-सामाजिक संस्कृति से निर्णायक संघर्ष करना ही होगा। नवीन मेहनतकश जन संस्कृति का उदय भारत की सरजमीन पर करने की खातिर राजसत्ता और समाज दोनों का ही मूलभूत चरित्र बदलना होगा। समाज में व्यापत घनघोर आर्थिक गैर बराबरी का खात्मा किए बिना राजसत्ता पर दौलत वालो के अप्रत्यक्ष आधिपत्य का खात्मा नहीं किया जा सकेगा। आम चुनाव में भ्रष्टाचार से अर्जित खरबों की काली दौलत के इस्तेमाल ने गणतंत्र को माफिया राजनेताओं का बंधुआ बनाकर रख दिया है। भारतीय गणतंत्र को वास्तव में मेहनतकशों के जनगण के गणतंत्र के तौर पर तशकील करने के लिए नृशंस भ्रष्टता का, अमानवीय सांप्रदायिकता एवं जातिवाद का और क्रूर आर्थिक गैरबराबरी को मुकम्मल खात्मा करना होगा।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)

Reproduced by www.nobbyshobby.com with author's permission